

आमजन को समुचित सेवाएं मिले, अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों को करें समुचित निर्वहन : सत्यानी

जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी ने किया जिले के मेलूसर में राजकीय विद्यालय तथा भादासर दिखनाता में पीएचसी का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को बधाई दी।

जिला कलक्टर सत्यानी ने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी अपने दायित्वों को समुचित निर्वहन करें तथा आमजन को समुचित सेवाएं मिलें। आमजन को सुविधाओं के लिए एसमिति रहते हुए कार्यकारी अपने दायित्वों का निरीक्षण करें। अब इकत्त्वा, बिजली, पानी आदि आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता के साथ आमजन की शिक्षायतों का निरीक्षण करें तथा आमजन की परेशानी के प्रति संवेदनशीलता बरतें। उन्होंने भादासर दिखनाता में पीएचसी के निरीक्षण के दौरान दवा उपलब्धता, चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, औपीड़ी व दवा वितरण के केन्द्र का अवलोकन किया और व्यवस्थाएं देखीं। उपस्थिति जांच के दौरान



पीएचसी में कुल 8 स्टाफ में से एमओआईसी डॉ प्रियंका सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक डॉ सुनील विवाही व डॉ अंशु अशोक कुमार सहित 3 कार्मिक अनुपस्थित मिले, जिस पर जिला कलक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई। पीएचसी में भौजूद ग्रामीणों ने अस्पताल के स्टाफ की अनुपस्थिति की शिक्षायत की, जिस पर जिला कलक्टर ने चिकित्सा वितरकों व मस्तिष्क स्टाफ की उपस्थिति, औपीड़ी व दवा वितरण के केन्द्र का अवलोकन किया और व्यवस्थाएं देखीं। उपस्थिति जांच के दौरान

जारी करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने पीएचसी परिसर व गांव में बिजली आपूर्ति की समस्या बताई, जिस पर जिला कलक्टर ने डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देश दिए।

विद्यालय का किया निरीक्षण, देखीं व्यवस्थाएं: इसी क्रम में जिला कलक्टर सत्यानी ने सरदारशहर के मेलूसर बीकान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समिति प्रबंधन करते हुए व्यवस्थाएं देखीं। हरा-चारा केन्द्र में किया पीछोरोपण: जिला कलक्टर सत्यानी ने सरदारशहर मुख्यालय

पर बीकानेर रोड स्थित हरा-चारा केन्द्र में पीछोरोपण किया तथा गोशाला समिति की व्यवस्थाएं देखीं। सत्यानी ने कहा कि हमें संकलित होकर प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का सुनिचित निर्वहन करना चाहिए।

प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन से हमें मानवता के लिए ग्लोबल वार्षिक जैसा खतरा खड़ा कर रखा है। अब गोशाला समिति में संशरण से ही हम मानवता के अस्तित्व का कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने गोशाला विद्यालय में येजल व चारे, तथा चिकित्सकीय व्यवस्था को जानकारी ली। पीछोरोपण के दौरान सरदारशहर एसडीएम मीनू वर्मा, तहसीलीयर तहसीलाल मोणा, डिस्कॉम एसडीएन शासिकांत मोणा, पीएचडी ईर्षण विजय सिंह, दीपक शर्मा, बनवारी लाल, सानिवि एसडीएन लखमीराज, जगराम चुम्हार, पवन कुमार चंद्रेन सोलाराम, परवन चुम्हार, गिरधरीलाल पारीक, जारीनी, गिरसंगसरिया सहित अन्य उपस्थित रहे।

प्रत्रकार कॉलोनी, सामुदायिक केन्द्र में जोन ऑफिस खोलने के विरोध में जनहित याचिका दायर, याचिका पर सुनवाई आज

बढ़ता राजस्थान

की गई है। इस पर सुनवाई 25 जुलाई को होगी, समिति अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि जेडीए अधिकारियों की हठधार्मिकों के चलते कर्मचारियों को जलदबाजी में सामुदायिक भवन में बैठा दिया गया है। समुदायिक केंद्र पर जेडीए द्वारा अवैध रूप से कार्यालय संचालन कर जनता को सुविधा से बचाते किया जा रहा है। इससे प्रत्रकार कॉलोनी और आस पास की कॉलोनीवासियों के लिए बड़ी समस्या बन गई है।

उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में प्रत्रकार कॉलोनी के लिए सामुदायिक केंद्र में जेडीए का जोन ऑफिस खोलने के विरोध में लापवंद और प्रदर्शन कर अपना रोप व्यक्त कर चुके हैं।

लोगों का कहना है कि सामुदायिक केंद्र में जनसुविधा को छोड़ने की अपीली वार्षिक धर्मों के लिए सामाजिक, धार्मिक, वैवाहिक और तीये कि बैठक जैसे आयोजन लिए बनाया गया है।

राजस्थान की पहली नगर पालिका 4 साल में दूसरी बैठक में आज लगेगी विकास की मोहर

बढ़ता राजस्थान

अंता (शास्की मंसूरी)।

राजस्थान की पहली नगर पालिका की 4 वर्ष में दूसरी बार आज गुरुवार को नगर पालिका मण्डल अन्ना की साधारण बोर्ड बैठक नगरपालिका कार्यालय में दिनांक: 25.07.2024 (गुरुवार) को रामेश्वर खंडेलाल 'अध्यक्ष' नगर पालिका अन्ना की अध्यक्षता में समय प्रति: 11:00 बजे आहुत की जानी है। जिसमें विकास के योग्य मूलक करने पर कार्यालय में नियुक्त वर्षों पर चर्चा की जायगी जिसमें नियम मुद्रे नारा पालिका अंता के चेयरमैन पद को लेकर गत 6 माह से हो रही उठा पटक के बाद 25 जुलाई गुरुवार को नगर पालिका अंता बोर्ड की बैठक 4 वर्ष के अंतिम बोर्ड की बैठक के बाद होने जा रही है। जिसमें भाजपा के रामेश्वर खंडेलाल कार्यालयक चेयरमैन के रूप से पैठनी के बाद अंतोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है। इस



से अतिक्रमण होने और नीलाम करने, नगरपालिका के सभी बार्डों में 20-20 लाख रुपये के नियमण एवं विकास कार्य का प्रस्ताव, राजकीय भूमि कब्जा नियमन के अंतर्गत जारी पटों की जांच, नियम संज्ञान के बाल वाले धूल धूर से नारा पालिका अंता के होने वाली इस प्रस्तावित बैठक में मुख्य रूप से नारा पालिका अंता बोर्ड की बैठक के बाद 25 जुलाई गुरुवार को नगर पालिका अंता बोर्ड की बैठक 4 वर्ष के अंतिम बोर्ड की बैठक के बाद होने जा रही है। जिसमें भाजपा के रामेश्वर खंडेलाल कार्यालयक चेयरमैन के रूप से पैठनी के बाद अंतोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है। इस अंतिम बोर्ड की बैठक के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

विद्यालय में कक्ष कक्ष मय बरामदा का उद्घाटन



बढ़ता राजस्थान

कोटपूली (नि.स.)।

कोटपूली के ग्राम मोहनपुर स्थित अल्ट्राटेक कार्यालयी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैंसलाल में कक्ष मय बरामदा का नियमण कर सुधारमध्ये किया गया। मुख्य अधिकारी इकाई प्रमुख नियन दुराके ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और जिसमें जिम्मेदारी के अंतर्गत ग्रामीण विकास की मोहर के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण से उड़े बच्चे देश का भविष्य हैं और जिसमें जिम्मेदारी के अंतर्गत ग्रामीण विकास की मोहर के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण से उड़े बच्चे देश का भविष्य हैं और जिसमें जिम्मेदारी के अंतर्गत ग्रामीण विकास की मोहर के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

कोटपूली के नियमण के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

नेतृत्व के नियमण के बाद अंदरोंने वाले धूल धूर से गांग में धूंध व कोहरे जैसा वातावरण बना रहा है।

सम्पादकीय

केंद्र ने युवाओं की ली सूध, मोदी सरकार का बजट उठानीदों से भेजा

जिस दौर में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में काफी उथल-पुथल और चिंताजनक हालात बने हुए हैं, उसमें मंगलवार को पेश बजट ने एक तरह से सबका ख्याल रखने का आश्वासन दिया है। बजट के कुछ अहम बिंदुओं को देखते हुए वह साफ लगता है कि तीसरी बार भर सत्र में आने के बाद नोर्ड मोदी के नेतृत्व वालों सरकार की प्राथमिकताएं में अब शायद कुछ बदलाव आया है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रवाधन किया गया है। यानी सरकार ने इसके लिए कुछ समय से देश की राजनीति में चुनावी मुद्दा बने, लेकिन प्रकाशन तक अविश्वसनीय सावलों की सुध लेने दिखाई है। देश में बोरोजारी की चुनावीयों से ज़ज़ने के लिए तीन नई योगानों की घोषणा की गई है, जिसमें अगले पांच वर्ष के लिए दो हजार करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौरी-हासिल करने वालों को सरकार उनके पहले महीने के बेतन पर बाहर की रूप में पंद्रह हजार रुपए तक की अतिरिक्त राशि देगी।

इसके अलावा, एक करोड़ युवाओं को पांच वर्ष में शीर्ष पांच से कंपनियों में प्रशिक्षण या इंटर्निंग का मौका देने की की गई है, जिसके तहत युवाओं को पांच वर्षों का भ्राता-भ्रातीया दिया जाएगा। यहाँ है, लंबे समय के बाद ऐसा लगता है कि बोरोजारी की सम्पत्ति की गंभीरता को स्वीकार करने की कोशिश की गई है। अमरपाल पर इस पर सबकी राह रही है कि बजट में मध्यवर्ग के लिए क्या कोई राहत है। इस लियोन के देवतों तो सरकार ने नई बार व्यवस्था की दरों में जो बदलाव किया है, उससे लोगों के साथ स्त्रह हजार रुपए तक बच सकते हैं और अब तीन लाख रुपए की आय को कोई अलाकर नहीं देना होगा। अप्रवक्ष कर की दरों में बदलाव के बाद अब केसर की कुछ दवाएँ मोबाइल फोन, सोना-चांदी के दाम में कमी आने की संभावना है।

मगर आम लोग जिस मंडगाई से ज़बू रहे हैं, उससे कितनी राहत मिलेगी, इस मसले पर कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान देने के अलावा नवानियों शहरी आवास योजना के तहत एन एन प्रवाधनों से मध्यवर्ग को लाभ मिल सकता है। इसी तरह, कर ढांचे के नए स्पर्श से ऐसों लगता है कि सरकार की मंसा लोगों का पैसा बचाने के बजाय खर्च करने का व्यवधान चुनावी की ओर प्रवर्त करने की है। अल्पकालिक पूँजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ के नियमों में हुए बदलाव का असर इस रूप में सामने आया कि बजट भाषण के द्वारा ही शीर्ष बाजार धड़ाम से गिर गए। एक उम्मीद थी कि पिछले कुछ समय से रेल यात्रा के सम्बन्ध तंत्रों को लेकर दूरी दूरी पर सवाल उठे थे, तो सरकार बजट में साधार इस पर ध्यान दे। मगर विचित्र यह है कि रेलवे क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। इस बजट में खासतौर पर बिहारी और आंप्र प्रदेश के लिए जिस तरह अलग से बदलाव किया गया है, उससे सबका ध्यान चींचा है। खासतौर पर बिहार के लिए छालीस बजट उठाई दी गई।

मगर आम लोग जिस मंडगाई से ज़बू रहे हैं, उससे कितनी राहत मिलेगी, इस मसले पर कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान देने के अलावा नवानियों शहरी आवास योजना के तहत एन एन प्रवाधनों से मध्यवर्ग को लाभ मिल सकता है। इसी तरह, कर ढांचे के नए स्पर्श से ऐसों लगता है कि सरकार की मंसा लोगों का पैसा बचाने के बजाय खर्च करने का व्यवधान चुनावी की ओर प्रवर्त करने की है। अल्पकालिक पूँजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ के नियमों में हुए बदलाव का असर इस रूप में सामने आया कि बजट भाषण के द्वारा ही शीर्ष बाजार धड़ाम से गिर गए। एक उम्मीद थी कि पिछले कुछ समय से रेल यात्रा के सम्बन्ध तंत्रों को लेकर दूरी दूरी पर सवाल उठे थे, तो सरकार बजट में साधार इस पर ध्यान दे। मगर विचित्र यह है कि रेलवे क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। इस बजट में खासतौर पर बिहारी और आंप्र प्रदेश के लिए जिस तरह अलग से बदलाव किया गया है, उससे सबका ध्यान चींचा है। खासतौर पर बिहार के लिए छालीस बजट उठाई दी गई।

बजट 2024-25 में चाबहार बंदरगाह के लिए क्यों खोला गया खजाना?

भारत क्षेत्रीय व्यापार खासकर अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह पर जोर दे रहा है। यह बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) परियोजना के एक प्रमुख केंद्र के तौर पर पेश किया गया है। आईएनएसटीसी परियोजना भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल-टुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी एक बहुस्तरीय परिवहन परियोजना है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने ईरान के साथ संपर्क परियोजनाओं पर भारत की अहमियत को रेखांकित करते हुए 2024-25 के लिए चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

अशोक भाटिया

भारत क्षेत्रीय व्यापार खासकर अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के नेंडलॉक अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया था। हालांकि ईरान के साथ समझौते को लेकर भारत पर दबाव आता रहा है। लेकिन भारत को इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ा है। यह 2024-25 के बजट में भी दिखा रहा है। वहाँ भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारत और ईरान के बीच चाबहार के शाहिद बेहिस्ती बंदरगाह के सामान्य कारों और कटेन टर्मिनलों के उपकरण और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए एक महवर्षी परागमन बंदरगाह के रूप में कार्य करती है, जो भूमि से पिछे हुए देश है। चाबहार बंदरगाह के लिए चाप तो संचालन के लिए अनुबंध के बावजूद ईरान के बीच चाबहार के शाहिद बेहिस्ती बंदरगाह की भूमि परेक्षण की थी। चाबहार बंदरगाह एक भारत-ईरान फ्लैटशिप परियोजना है जो आफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए एक महवर्षी परागमन बंदरगाह के रूप में कार्य करती है।

भारत और ईरान ने मई में ओमान की खाड़ी पर चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के नेंडलॉक अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया था। हालांकि ईरान के साथ समझौते को लेकर भारत पर दबाव आता रहा है। लेकिन भारत को इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ा है। यह 2024-25 के बजट में भी दिखा रहा है। वहाँ भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारत और ईरान के बीच चाबहार के शाहिद बेहिस्ती बंदरगाह के सामान्य कारों और कटेन टर्मिनलों के उपकरण और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए एक महवर्षी परागमन बंदरगाह के रूप में कार्य करती है।



वेदतर तरीके से समझता है। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे। ये पूछे पर कि क्या इसका मतलब है कि भारत की निर्भरता पाकिस्तान पर कम हो सकती है। 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच इंटरनेशनल ट्रेड कारिंडोर को लेकर समझौता हुआ था। इसके कारिंडोर में चाबहार को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद भारत ने शाहिद बेहिस्ती का काम तेज कर दिया था। शाहिद बेहिस्ती के पहले फेन का काम दिसंबर 2017 में पूरा हो गया था। तभी भारत ने यहीं से अफगानिस्तान तक गंहे की पहली खोंभेजी थी। 2019 में पहली बार चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से कोई सामान भारत आया था। शाहिद बेहिस्ती के बीच चाबहार पोर्ट का काम संभाल रहा है। लेकिन ये शॉर्ट-टर्म एपीमेट था। समय-समय पर इसका असर नहीं होता है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2018 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर्म एपीमेट हो गया है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2019 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर्म एपीमेट हो गया है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2020 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर्म एपीमेट हो गया है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2021 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर्म एपीमेट हो गया है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2022 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर्म एपीमेट हो गया है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2023 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर्म एपीमेट हो गया है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2024 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर्म एपीमेट हो गया है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2025 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर्म एपीमेट हो गया है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2026 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर्म एपीमेट हो गया है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2027 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर्म एपीमेट हो गया है। इसके बाद भारत ने यहीं से एक बड़ा ट्रेन का दिसंबर 2028 में लाभार्ड 12 करोड़ 300 साल के लिए लाना-टर

